

भारत सरकार  
व ध और याय मं तलय  
याय वभाग  
लोक सभा

अतारां कत सं. 327

जिसका उ तर गु वार 25 फरवर, 2016 को दया जाना है

नःशु क व धक्काहायता

327. मोह मदफैज़ल :

ीदु यंतचौटाला :

ीआरो पा थ पन्न

एडवोकेट जोएस जॉज :

या व धौर याय मं ीयह बताने क कृपा कर गे क:

(क) देश म समाज के गर बऔर कमजोर वग को नःशु क व धक्काहायता दान करने के काय म लगे ा धकरप्सं थाओंका यौरा या है ;

(ख) या सरकार रा य व धकसेवा ा धक्का (एनोएओएलोएसोए) स हत इन ा धकरप्सं थाओंको सु ढबनाने पर वचारकर रह है और य दहां, तो त संबंधी यौरा या है ;

(ग) पछलेतीन व म येक्वष और चालू वष के दौरान इसके लएआवं टतऔर जार न्धसथा एनएएलएसए स हतइन ा धकरप्सं थाओं वारउपयोग क गई धनरा शका रा ष्मंघ रा य -वार यौरा या है ;

(घ) या एनएएलएसए स हतइन ा धकरप्सं थाओंके काय करप्काय न पादन क नगरानीकरने के लएसरकार के पास कोई तं है ता कइस कारआवं टत न यका समु चतउपयोग सु नचित कयाजा सके तथा अं तम यो ताओंबोषकर वचाराधीन कै दय यौन उ पीड़न कृतकआपदा पी इतको मदद करने के लए व भ काय म का बेहतर और कारगर काया वयन्मु नचित कयाजा सके ; और

(ङ) य दहां, तो त संबंधी यौरा या है और य दनह, तो इस संबंद् म सरकार वारा याकदम उठाए गये/जा रहे ह ?

उ तर

व ध और याय मं (ीी डी वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख) : व धक सेवा ा धकरण अध, ~~नःशु~~ वारा अध नयम क धारा 12 के अधीन पा यितय को नःशु व धक सेवाएं दान करने के लए सभी तर

पर तालुका यायालय से उच्चतम यायालय तक व धक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। जिसके अंतर्गत तालुका व धक सेवा, उच्चतम यायालय की व धक सेवा समेत, उच्चतम यायालय की व धक सेवा समेत व धक सेवा। धक सेवा व धक सेवा समेत तालुका व धक सेवा समेत भी है। उच्चतम व धक सेवाओं में यायालय, शक का संदाय अधिवक्ता उपलब्ध कराने और पेपर कार्य को तैयार करना इत्यादि सामिल है।

राज्य व धक सेवा अधिनियम ने राज्यालय व धक सेवा (अधिवक्ता और समेत व धक सेवा) अधिनियम 2010 अधिसूचित किया है जो उपरोक्त तालुका व धक सेवा और समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, यम हलाकों बालक इत्यादि को उच्चतम व धक सहायता प्रदान करता है। व धक सेवा संस्थाएं उन सभी व्यक्तियों को व धक सेवाएं प्रदान करने के लिए अहम प्रदेश यायालय के मामले में अधिवक्ता अथवा तालुका व धक सेवा के लिए सभी तालुका व धक सेवा पर जिसके अंतर्गत उच्चतम यायालय और उच्चतम यायालय भी व धक सहायता मामले के लिए अधिवक्ता पैनल वकालत नियुक्त करती है।

(ग) राज्यालय व धक सेवा अधिनियम (ए एल एस ए), व धक सेवा अधिनियम अधिनियम 1978 के धारा 4 के अधीन व धक सेवा अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार (व धक और यायम) अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम को पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2012-13, 2013-14, 2014-15 और वतमान व तीसरे 2015-16 के लिए आबंटित नगद न लखत है।